



## NEWSMAKERS

### शुगरकेन हार्वेस्टर मार्केट 2035 तक 5.0 बिलियन तक पहुंच जाएगा

नई दिल्ली : ऑटोमेशन, चीनी की बढ़ती मांग और लेबर की कमी की वजह से शुगर केन हार्वेस्टर मार्केट के लगातार बढ़ने का अनुमान है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और सरकारी मशीनीकरण को बढ़ावा देने से खास इलाकों, खासकर APAC और साउथ अमेरिका में इसे अपनाने में तेजी आ रही है, जिससे लंबे समय तक खेती की प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट मिल रहा है।

इंडस्ट्री टुडे के मुताबिक, 2024 में शुगर केन हार्वेस्टर मार्केट की वैल्यू 3.27 USD बिलियन थी और 2025 में इसके 3.4 USD बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो अनुमानित समय में 3.9 प्रतिशत के CAGR से 2035 तक 5.0 USD बिलियन तक और बढ़ जाएगा। यह लगातार बढ़ती दुनिया भर के खेती के सेक्टर में मशीनीकरण की तरफ बदलाव को दिखाती है ताकि काम करने की क्षमता में सुधार हो, हाथ से काम करने पर निर्भरता कम हो और कटाई की प्रोडक्टिविटी बढ़े। चीनी, एथेनॉल और बायोफ्यूल फीडस्टॉक की बढ़ती दुनिया भर में मांग गन्ने के उत्पादन को बढ़ा रही है, जिसका सीधा असर एडवांस्ड कटाई के इक्विपमेंट को अपनाने पर पड़ रहा है। मैकेनाइज्ड हार्वेस्टर तेजी से कटाई करते हैं, फसल की रिकवरी साफ होती है, और ऑपरेशनल नुकसान कम होता है, जिससे वे मॉडर्न शुगर फार्मिंग में एक ज़रूरी हिस्सा बन जाते हैं।

कटिंग की चौड़ाई के आधार पर, कमर्शियल शुगर प्लांटेशन के लिए ज़्यादा कटिंग रेंज वाले हार्वेस्टर ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं क्योंकि वे कटाई की स्पीड बढ़ाते हैं और ऑपरेशन का समय कम करते हैं। हालांकि, सरकारी सब्सिडी और मशीनीकृत खेती को बढ़ावा देने वाले फाइनेंसिंग प्रोग्राम की वजह से छोटे और मीडियम साइज़ के फार्म में अच्छी ग्रोथ होने की उम्मीद है।



मार्केट के बढ़ने में कई मुख्य वजहें हैं। मुख्य वजहों में से एक है खेती में काम करने वाले मजदूरों की बढ़ती लागत और कमी, जो किसानों को मशीनीकृत कटाई के तरीके अपनाने के लिए बढ़ावा दे रही है। ऑटोमेशन हाथ से काम करने वाले मजदूरों पर निर्भरता कम करता है और कटाई की स्पीड और एक जैसा काम करने में सुधार करता है। इसके अलावा, चीनी और एथेनॉल की बढ़ती ग्लोबल खपत की वजह से चीनी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जिससे एडवांस्ड कटाई के इक्विपमेंट की मांग बढ़ रही है। सब्सिडी, टैक्स में छूट और मशीनीकरण प्रोग्राम के रूप में सरकारी मदद भी इसे अपनाने में तेजी ला रही है, खासकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में।

बायोफ्यूल प्रोडक्शन में बढ़ती एक और बड़ा ट्रेंड है जो मार्केट की ग्रोथ को बढ़ा रहा है। गन्ना एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए एक मुख्य फीडस्टॉक है, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर दुनिया भर में बढ़ते जोर से गन्ने की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। जैसे-जैसे बायोफ्यूल प्रोडक्शन बढ़ेगा, कुशल हार्वेस्टिंग मशीनरी की मांग में काफी बढ़ती होने की उम्मीद है। इसके अलावा, मैनुफैक्चरर ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए, कम एमिशन और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी वाली एनवायरनमेंट के हिसाब से सस्टेनेबल मशीनें बनाने पर फोकस कर रहे हैं।

नतीजा यह है कि शुगर केन हार्वेस्टर मार्केट 2035 तक लगातार ग्रोथ के लिए तैयार है, जिसे ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और बढ़ते चीनी और बायोफ्यूल प्रोडक्शन से सपोर्ट मिलेगा। एशिया-पैसिफिक, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के उभरते बाजारों में ग्रोथ के बड़े मौके हैं, जबकि डेवलपड इलाकों को एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी से फायदा मिल रहा है। जैसे-जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ने और लेबर की कमी को दूर करने के लिए मशीनीकरण ज़रूरी होता जाएगा, वैसे-वैसे शुगर केन हार्वेस्टर ग्लोबल एग्रीकल्चर के भविष्य में अहम भूमिका निभाएंगे।

Source: Chinimandi, 3<sup>rd</sup> March 2026

### वैश्विक कीमतों के दबाव से भारत का चीनी निर्यात सुस्त, 20 लाख टन कोटा के मुकाबले फरवरी तक केवल 3.15 लाख टन निर्यात

सरकार द्वारा 2025-26 सब के लिए 20 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति देने के बावजूद भारत ने फरवरी 2026 तक केवल लगभग 3,15,517 टन चीनी का निर्यात किया है। भारतीय निर्यात कीमतों की तुलना में अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कम कीमतें रहने के कारण निर्यात की रफ्तार धीमी पड़ी है।

वर्ष 2025-26 चीनी सीजन (अक्टूबर-सितंबर) के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत निर्यात कोटे की तुलना में भारत का चीनी निर्यात काफी पीछे चल रहा है। फरवरी 2026 के अंत तक केवल 3,15,517 टन चीनी का निर्यात हुआ है, जबकि सरकार ने पूरे सीजन में 20 लाख टन निर्यात की अनुमति दी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि चीनी उद्योग ने ही सरकार से इस सीजन में 20 लाख टन निर्यात की अनुमति देने का



अनुरोध किया था। शिपमेंट की रफ्तार धीमी रहने का मुख्य कारण यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतें भारतीय निर्यात कीमतों से कम हैं, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धा नहीं रह गया है।

निर्यात गंतव्यों के आंकड़े बताते हैं कि इस सीजन में भारत से होने वाले चीनी निर्यात का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया और पड़ोसी क्षेत्रों में गया है। कुल निर्यात में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की हिस्सेदारी 25.4% रही, इसके बाद अफगानिस्तान 22.9% के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अन्य प्रमुख गंतव्यों में जिबूती (14.6%), तंजानिया (6.8%) और श्रीलंका (6.5%) शामिल हैं।

Source: RuralVoice, 16<sup>th</sup> March, 2026



## केंद्र सरकार ने अप्रैल के लिए 23 एलएमटी चीनी का मासिक कोटा जारी किया

नई दिल्ली : 25 मार्च को की गई घोषणा में खाद्य मंत्रालय ने अप्रैल 2026 के लिए 23 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चीनी का मासिक कोटा निर्धारित किया, जो मार्च 2026 के 22.5 एलएमटी के कोटे से अधिक है। जबकि, अप्रैल 2025 में सरकार ने घरेलू बिक्री के लिए 23.5 एलएमटी का मासिक चीनी कोटा निर्धारित किया था।



Source: ChiniMandi, 25<sup>th</sup> March, 2026

## यूपी में पहली बार महिला गन्ना किसानों को मिली मजबूती, बीज उत्पादन से करोड़ों का कारोबार, जानें कैसे?

उत्तर प्रदेश में गन्ना की खेती के क्षेत्र में महिलाओं ने अभूतपूर्व सफलता हासिल करते हुए नया इतिहास रच दिया है। योगी सरकार में प्रदेश की 57 हजार से अधिक ग्रामीण महिलाएं गन्ना उत्पादन से जुड़कर सफल उद्यमी बन चुकी हैं। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिली है। प्रदेश में वर्ष 2020-21 में शुरू किए गए 'उन्नत गन्ना बीज वितरण कार्यक्रम' से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। इस योजना के तहत 37 गन्ना आच्छादित जिलों में 3,163 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। इनमें 57,322 महिलाओं को स्वरोजगार मिला है। साथ ही इस पहल से अब तक लगभग साढ़े चार लाख से अधिक रोजगार पैदा हुए हैं।

### महिलाओं को मिली प्राथमिकता, बढ़ा आत्मविश्वास

मामले में गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने बताया कि गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में पहली बार योगी सरकार के दौरान महिला किसानों को पूर्ण प्राथमिकता दी गई है। इससे प्रदेश की लगभग डेढ़ लाख महिला गन्ना लघु किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। इस निर्णय ने महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाया है और उन्हें खेती में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया है।

### महिलाओं की आर्थिक स्थिति हुई मजबूत

गन्ना आयुक्त ने बताया कि इस योजना में सामाजिक समावेशन का भी विशेष ध्यान रखा है। इसमें 10,270 अनुसूचित जाति और 130 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को शामिल किया गया है, जो अब आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं।

### समूहों ने अब तक तैयार किए 60.73 करोड़ गन्ना बीज

महिला स्वयं सहायता समूहों ने अब तक 60.73 करोड़ गन्ना बीज तैयार किए हैं। इसके बदले उन्हें 77.83 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है। इससे ग्रामीण महिलाओं को बड़े स्तर पर आर्थिक लाभ मिला है और वे अब कृषि आधारित उद्यमिता की नई पहचान बना रही हैं और इससे गांवों में आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिली है।

### महिलाओं को ऋण और अन्य सुविधाएं

गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने बताया कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए गन्ना विभाग ने ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ एक एमओयू किया है। जिसके तहत समितियों में प्रेरणा कैंटीन चलाई जाएंगी। इसके अंतर्गत महिलाओं को ऋण एवं अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उनके रोजगार एवं आय में वृद्धि होगी।

Source: KisanTak, 26<sup>th</sup> March, 2026



## BALRAMPUR CHINI WINS FIRST MAJOR ORDER TO SUPPLY ECO-FRIENDLY BIOPLASTICS TO LUCKNOW CANTONMENT BOARD

Balrampur Chini Mills Ltd has secured its first large institutional order for eco-friendly bioplastic products. The order comes from the Lucknow Cantonment Board, marking an important step in the company's new green business journey.

The company, which is one of India's leading sugar producers, is expanding into the bioplastics sector. It is setting up a Polylactic Acid (PLA) manufacturing plant in Kumbhi, Uttar Pradesh, with an annual production capacity of 80,000 tonnes. The plant is expected to begin operations in October this year.

Under this first official order, Balrampur Chini will supply compostable garbage bags (in two sizes), 300 ml PLA bottles, 3D-printed compostable PLA pens, and PLA folders. All these products are made from renewable, plant-based material that is 100% compostable, leaves no microplastics, and has a lower carbon footprint compared to traditional plastic.

The Lucknow Cantonment area, which covers around 6,760 acres, is managed by the Cantonment Board under the Ministry of Defence. By placing this order, the Board is showing confidence in bio-based alternatives and supporting the shift away from conventional fossil-fuel-based plastics.

Avantika Saraogi, Executive Director of Balrampur Chini Mills, said the order is more than just a business achievement. According to her, it reflects growing trust in India's developing biopolymer industry and proves that sustainable materials are now reliable options for large-scale institutional use.

This development highlights a broader move toward sustainable solutions as concerns over single-use plastics and microplastic pollution continue to rise.

Source: SugarTime, 25<sup>th</sup> February, 2026

## E20 PETROL TO BECOME MANDATORY FROM APRIL 1; MAIZE FARMERS EXPECTED TO BENEFIT

The Government of India has decided to make 20% ethanol-blended petrol (E20) mandatory across the country starting April 1, 2026. This move is expected to create new

opportunities for maize farmers because maize is widely used in the production of ethanol. As demand for ethanol increases, the demand for maize is also likely to rise, which could significantly boost farmers' incomes.

Speaking at the Pusa Krishi Vigyan Mela organized by the Indian Agricultural Research Institute, agricultural expert Dr. Ramniwas from the Indian Institute of Maize Research in Ludhiana explained that earlier petrol contained 10% ethanol blending. However, from April 1, 2026, the ethanol blend will increase to 20%.

Currently, the country relies heavily on imports for petrol and crude oil. Increasing ethanol blending will help reduce dependence on foreign fuel, while also supporting domestic agriculture.

As ethanol production grows, maize cultivation is expected to expand, giving farmers better market demand and higher profits. The government has also set a long-term goal of achieving 30% ethanol blending by 2030, which could further increase income opportunities for farmers.

Source: SugarTimes, 7<sup>th</sup> March, 2026

## RISE IN INDUSTRIAL DIESEL PRICES AFFECTS SUGAR MILLS

New Delhi: A sharp increase in industrial diesel prices has raised concerns across the sugar sector, with industry officials warning of higher costs and possible delays in farmer payments, Business Standard reported.

The price of industrial diesel has jumped to about Rs 112 per litre from Rs 92.68, marking a rise of Rs 19.32 per litre with immediate effect. The hike is expected to significantly raise transportation expenses for sugar mills, which depend heavily on diesel for procuring sugarcane, managing logistics and could affect their ability to make timely payments of the fair and remunerative price (FRP) to farmers.

In a communication to the government, the Indian Sugar & Bio-Energy Manufacturers Association highlighted the growing burden of input costs and cautioned that frequent changes in fuel prices are affecting the sector's financial stability.

Source: Chinimandi, 23<sup>rd</sup> March, 2026



## DECLINING TREND IN SUGARCANE AVAILABILITY



Lucknow: This is no sweetener for Uttar Pradesh. The country's largest sugar-producing state is facing a decline in sugarcane availability for crushing, raising concerns over a potential dip in sugar output in the 2025-26 season.

The shortfall, estimated to be between 2-3%, has been attributed to an unusual spike in temperatures in Feb, followed by unseasonal rains in March, along with crop damage caused by rot in the widely cultivated Co-0238 cane variety. The situation has already led to a host of mills shutting down their operations, raising fears of a dip in sugar production. The latest is Unn sugar mill in Shamli, which closed its operations on the intervening night of March 23 and 24, almost 15 days before its scheduled closure time.

Likewise, the Thana Bhawan sugar mill too is expected to shut its operations later this week, reports said.

The mill has already issued a notice on March 20 vis-a-vis lesser availability of cane for crushing. Both the mills received almost 25 lakh quintals less cane this season, prompting the mill operators to close down their operations before time, sources said.

Likewise, the Oswal mill in Nawabganj, Bahari sugar mills, Dhampur mill, Kisan Sahkari mill and Dwarikesh mills too raised concern over scarce of cane for quality.

The poor of cane has further aggravated the situation, leading to a decline in sugar recovery rates and making operations unviable for a host of mills.

An official in the UP Sugar Mills Association said that the actual situation is expected to appear in another 10 to 15 days when the cane crushing ends for the 2025-26 season.

Source: TOI, 27<sup>th</sup> March, 2026

ZONE	31st March'2026			Sugar Production (Lac Tons)	31st March'2025			Sugar Production (Lac Tons)
	Number of Factories Started	Number of Factories Closed	Number of Factories Operating		Number of Factories Started	Number of Factories Closed	Number of Factories Operating	
U.P.	121	93	28	87.50	122	74	48	87.50
Maharashtra	210	208	2	99.30	200	194	6	80.26
Karnataka	81	79	2	47.90	80	79	1	39.94
Gujarat	14	12	2	7.10	15	7	8	8.50
Tamil Nadu	30	15	15	5.00	30	16	14	4.29
Others	83	76	7	25.51	87	69	18	28.29
ALL INDIA	539	483	56	272.31	534	439	95	248.78

(Note: Above sugar production figures are after diversion of sugar into ethanol)

## Do You Know

### THE EVOLUTION OF INDIAN CURRENCY

PHOOTI KAUDI = 1 KAUDI  
10 DUI = 1 DUMRI  
2 DUMRI = 1 DHELA  
1.5 PIE = 1 DHELA  
3 PIE = 1 PAISA  
4 PAISA = 1 ANNA  
16 ANNA = 1 RUPAYA

UPSMA Newsletter titled 'Varta' the Dialogue is providing information on sugar, sugar industry and sugar byproducts. We request you to share your thoughts and experience with us through write-ups, success stories, updates, photographs etc. We publish your creative in the next edition of this newsletter. You are requested to send your entries to be published in UPSMA newsletter through mail at [upsma@upsma.org](mailto:upsma@upsma.org). The newsletter will be uploaded on UPSMA website.

**अस्वीकरण:** यहाँ दी गई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा या अन्य स्रोतों से ली गई है, जिन्हें विश्वसनीय माना जाता है और इस पर इस तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इस समाचार में दी गई जानकारी में किसी भी अनजाने त्रुटि से किसी भी व्यक्ति को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए 'वार्ता टीम' किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगी। इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी इस समाचार की तारीख तक है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य के परिणाम या घटनाएँ इस जानकारी के अनुरूप होंगी।